KGS IAS

KHAN GLOBAL STUDIES

Most Trusted Learning Platform

KHAN SIR

Most Trusted Learning Platform

# CURRENT AFFAIRS DISCUSSION

❖ Political party and Symbol

✓ Who allots election symbols to political parties in India?

➢ The Election Commission of India has the power under The Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968

❑ Two types of symbols

➢ Exclusive Symbol – Reserved for recognised political parties

➢ Free Symbol – Can be used by any other non-recognised political party or candidates (It is not permanent)

❖ राजनीतिक दल और प्रतीक

✓ भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है?

➢ आयोग को चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के तहत शक्ति प्राप्त है

❑ दो प्रकार के प्रतीक

➢ विशिष्ट प्रतीक - मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित

➢ निःशुल्क प्रतीक- किसी अन्य गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल या उम्मीदवारों द्वारा उपयोग किया जा सकता है (यह स्थायी नहीं है)

# UPSC

- EC is also empowered to look into any dispute related to symbol, party name etc.

- चुनाव आयोग को प्रतीक, पार्टी के नाम आदि से संबंधित किसी भी विवाद को देखने का भी अधिकार है।

## ❖ CHICAGO CONVENTION

- It establishes the privileges and obligations of all contracting States
- It established the International Civil Aviation Organization (ICAO)
- It is a specialized agency of the United Nations charged with coordinating international air travel.
- It establishes rules of airspace, aircraft registration and safety, security, and sustainability, and details the rights of the signatories in relation to air travel.

## ❖ शिकागो कन्वेंशन

- यह सभी अनुबंधित राज्यों के विशेषाधिकारों और दायित्वों को स्थापित करता है
- इसने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) की स्थापना की
- यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा का समन्वय करने की जिम्मेदारी है।
- यह हवाई क्षेत्र, विमान पंजीकरण और सुरक्षा, सुरक्षा और स्थिरता के नियम स्थापित करता है, और हवाई यात्रा के संबंध में हस्ताक्षरकर्ताओं के अधिकारों का विवरण देता है।

## ✓ New Changes

- It refrains member States from resorting to the use of weapons against civil aircraft in flight.
- It calls for raising the strength of the ICAO Council from 36 to 40.
- It calls for raising the strength of the Air Navigation Commission from 18 to 21

## ✓ नये परिवर्तन

- यह सदस्य देशों को उड़ान में नागरिक विमानों के खिलाफ हथियारों के इस्तेमाल से रोकता है।
- इसमें आईसीएओ काउंसिल की ताकत 36 से बढ़ाकर 40 करने का आह्वान किया गया है।
- इसमें एयर नेविगेशन कमीशन की ताकत 18 से बढ़ाकर 21 करने का आह्वान किया गया है।

- FATF suspends Russia's Membership
- ✓ What is FATF?

- The global money laundering and terrorist financing watchdog
- An intergovernmental body (39 Countries including India) established through the G7 summit
- FATF is a task force composed of member governments who agree to fund the FATF on a temporary basis with specific goals and projects (a "mandate").
- The FATF Secretariat (currently 40 people) is housed administratively at the OECD.

- एफएटीएफ ने रूस की सदस्यता निलंबित कर दी
- ✓ एफएटीएफ क्या है?

- वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण निगरानी संस्था
- G7 शिखर सम्मेलन के माध्यम से एक अंतरसरकारी निकाय (भारत सहित 39 देश) की स्थापना की गई
- एफएटीएफ सदस्य सरकारों से बनी एक टास्क फोर्स है जो विशिष्ट लक्ष्यों और परियोजनाओं ("जनादेश") के साथ अस्थायी आधार पर एफएटीएफ को वित्त पोषित करने के लिए सहमत होती है।
- एफएटीएफ सचिवालय (वर्तमान में 40 लोग) प्रशासनिक रूप से ओईसीडी में स्थित है।

- The decision-making body of the FATF is known as its plenary, which meets thrice a year.
- World Bank, some offices of the United Nations and regional development banks also participate in its meeting as observers.
- To assess the strength of anti-money laundering and anti-terror financing frameworks of different countries

- एफएटीएफ की निर्णय लेने वाली संस्था को इसके पूर्ण सत्र के रूप में जाना जाता है, जिसकी साल में तीन बार बैठक होती है।
- इसकी बैठक में विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र के कुछ कार्यालय और क्षेत्रीय विकास बैंक भी पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेते हैं।
- विभिन्न देशों के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी-टेरर फाइनेंसिंग ढांचे की ताकत का आकलन करना

❖ **Lists of FATF**

✓ **Black List: Call for Action**

➢ It features countries that the group has considered non-cooperative in the global fight against money laundering and terror financing.

➢ **Countries:** North Korea, Myanmar and Iran

➢ **Grey List:** Other monitored jurisdictions

➢ It features countries where the FATF trains a bigger lens on the financial goings-on of a country to ensure they are meeting the recommendation criteria set out by the organisation.

➢ Currently, there are 23 countries on the grey list

❖ **FATF की सूचियाँ**

✓ **काली सूची: कार्रवाई के लिए कॉल**

➢ इसमें वे देश शामिल हैं जिन्हें समूह ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में असहयोगी माना है।

➢ **देश:** उत्तर कोरिया, म्यांमार और ईरान

➢ **ग्रे सूची:** अन्य निगरानी क्षेत्राधिकार

➢ इसमें उन देशों को शामिल किया गया है जहां एफएटीएफ किसी देश की वित्तीय गतिविधियों पर एक बड़ा नजरिया रखता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे संगठन द्वारा निर्धारित अनुशंसा मानदंडों को पूरा कर रहे हैं।

➢ फिलहाल ग्रे लिस्ट में 23 देश हैं

## ❖ GLOBAL BIOFUEL ALLIANCE

- GBA is a multi-stakeholder alliance of Governments, International Organizations and Industries
- It brings together the biggest consumers and producers of biofuels and interested Countries from the Global South to drive the development and deployment of biofuels
- It aims to position biofuels as a key to energy transition.
- Nineteen countries and 12 international organizations have already agreed to join or support the GBA.
- The alliance will also act as a central repository of knowledge and an expert hub.

## ❖ वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन

- जीबीए सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और उद्योगों का एक बहु-हितधारक गठबंधन है
- यह जैव ईंधन के विकास और तैनाती को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक दक्षिण से जैव ईंधन के सबसे बड़े उपभोक्ताओं और उत्पादकों और इच्छुक देशों को एक साथ लाता है।
- इसका उद्देश्य जैव ईंधन को ऊर्जा संक्रमण की कुंजी के रूप में स्थापित करना है।
- उन्नीस देश और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन पहले ही जीबीए में शामिल होने या समर्थन करने के लिए सहमत हो चुके हैं।
- गठबंधन ज्ञान के केंद्रीय भंडार और विशेषज्ञ केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा।

## ❖ Social Stock Exchange

- A social stock exchange is a platform where social enterprises/organizations can raise funds from the public.
- Just like equity, commodities, derivatives, and small and medium-sized enterprises (SMEs), the social stock exchange will be a segment on the stock exchange.
- Both BSE and NSE have received approvals to run an SSE.
- Organizations listed on the SSE can be For-profit Social Enterprises (FPEs) and Not-for-profit Organizations (NPOs)

## ❖ सोशल स्टॉक एक्सचेंज

- सोशल स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा मंच है जहां सामाजिक उद्यम/संगठन जनता से धन जुटा सकते हैं।
- इक्विटी, कमोडिटी, डेरिवेटिव और छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) की तरह, सोशल स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज पर एक खंड होगा।
- बीएसई और एनएसई दोनों को एसएसई चलाने की मंजूरी मिल गई है।
- एसएसई पर सूचीबद्ध संगठन फ़ायदेमंद सामाजिक उद्यम (एफपीई) और गैर-लाभकारी संगठन (एनपीओ) हो सकते हैं।

## ❖ Zero Coupon Zero Principal (ZCZP) bonds

- A new instrument called Zero Coupon Zero Principal (ZCZP) bonds has been conceived and approved.
- These have a zero coupon and no principal payment at maturity
- It may be issued to NPOs for social development projects/activities, in which the NPO has demonstrated expertise.
- ZCZP may not offer financial returns to the investor like conventional investment instruments, but they come with the promise of a social return on the investment to the funder.

## ❖ जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल (ZCZP) बांड

- जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल (जेडसीजेडपी) बांड नामक एक नए उपकरण की कल्पना और अनुमोदन किया गया है।
- इनमें शून्य कूपन होता है और परिपक्वता पर कोई मूल भुगतान नहीं होता है
- इसे सामाजिक विकास परियोजनाओं/गतिविधियों के लिए एनपीओ को जारी किया जा सकता है, जिसमें एनपीओ ने विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया है।
- ZCZP पारंपरिक निवेश साधनों की तरह निवेशक को वित्तीय रिटर्न की पेशकश नहीं कर सकता है, लेकिन वे फंडर को निवेश पर सामाजिक रिटर्न के वादे के साथ आते हैं।

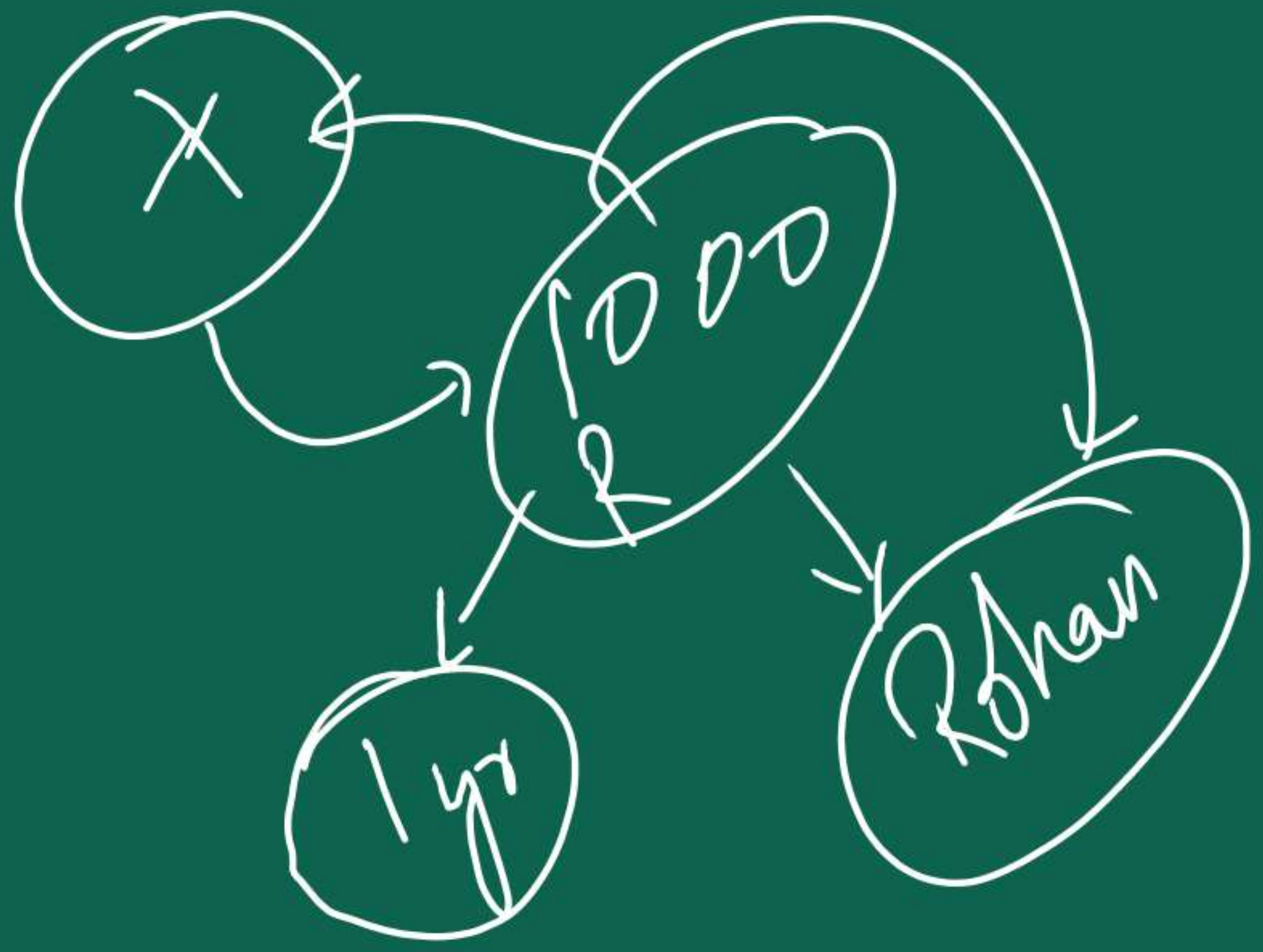
X
1000
R
1yr
Rohan

❖ **Mahila Samman Savings Certificate**

- The Mahila Samman Savings Certificate 2023 is available for two years, from April 2023-March 2025.
- **Eligibility:** The Mahila Samman Savings Certificate can be done only in the name of a girl child or woman. A woman or the guardian of a minor girl child can open a Mahila Samman Saving Certificate scheme.
- Investment – Min 1,000 and max – 2 lakhs
- No subsequent deposit shall be allowed in that account.
- It will offer a fixed interest rate of 7.5% Per Annum Compounded Quarterly

❖ **महिला सम्मान बचत पत्र**

- महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र 2023 अप्रैल 2023-मार्च 2025 तक दो वर्षों के लिए उपलब्ध है।
- **पात्रता:** महिला सम्मान बचत पत्र केवल किसी बालिका या महिला के नाम पर ही बनाया जा सकता है। एक महिला या नाबालिग बच्ची के अभिभावक महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना खोल सकते हैं।
- निवेश - न्यूनतम 1,000 और अधिकतम - 2 लाख
- उस खाते में बाद में कोई जमा राशि की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- यह प्रति वर्ष त्रैमासिक चक्रवृद्धि 7.5% की निश्चित ब्याज दर की पेशकश करेगा

- The account holder shall be eligible to withdraw a maximum up to 40% of the Eligible Balance once after the expiry of one year from the date of opening of the account but before the maturity of the account.
- The Customer can open multiple accounts under this scheme, however, 2nd account can be opened only after a time gap of three months from the date of opening of 1st account and so on. However total deposit including all the accounts should not exceed Rs 2 Lacs.

- खाताधारक खाता खोलने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद लेकिन खाते की परिपक्वता से पहले एक बार पात्र शेष राशि का अधिकतम 40% तक निकालने के लिए पात्र होगा।
- ग्राहक इस योजना के तहत कई खाते खोल सकता है, हालांकि, दूसरा खाता पहला खाता खोलने की तारीख से तीन महीने के अंतराल के बाद ही खोला जा सकता है। हालाँकि सभी खातों सहित कुल जमा राशि 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

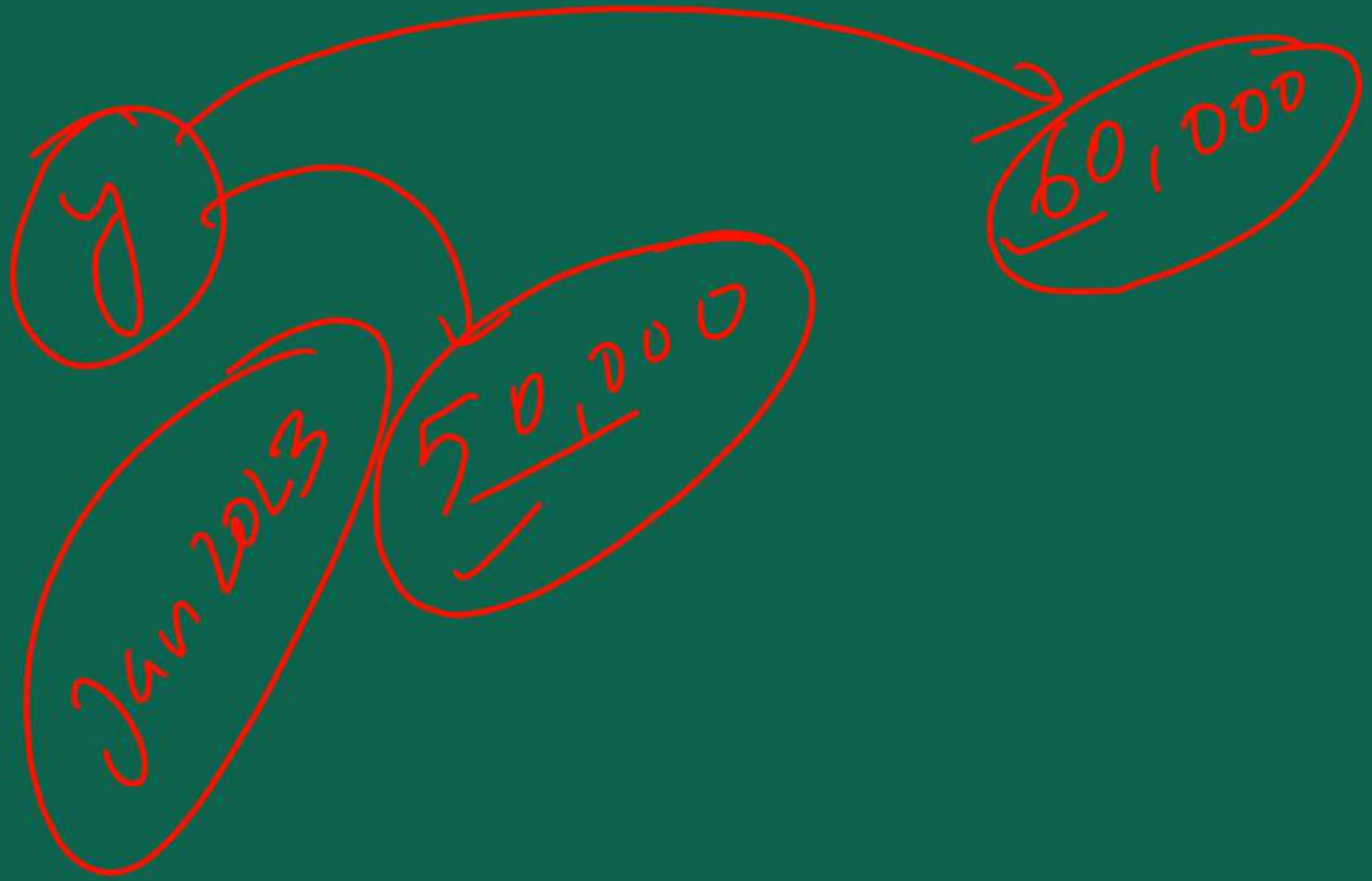
y
Jan 2013
50,000
60,000

## ❖ VIBRANT VILLAGES PROGRAMME (VVP) SCHEME

- A Centrally Sponsored Scheme
- Concerned Ministry: Ministry of Home Affairs
- For the development of villages on the northern border
- States covered: Himachal Pradesh, Uttarakhand, Arunachal Pradesh, Sikkim and Ladakh.
- The district administration with the help of Gram Panchayats will prepare the Vibrant Village Action Plans
- The objective of the programme is the comprehensive development of these villages to improve the quality of life of people & thereby reversing outmigration.

## ❖ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) योजना

- एक केन्द्र प्रायोजित योजना
- संबंधित मंत्रालय: गृह मंत्रालय
- उत्तरी सीमा पर गांवों के विकास के लिए
- कवर किए गए राज्य: हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख।
- जिला प्रशासन ग्राम पंचायतों की मदद से वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान तैयार करेगा
- कार्यक्रम का उद्देश्य इन गांवों का व्यापक विकास करना है ताकि लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके और इस प्रकार पलायन को रोका जा सके।

- ❖ **MISHTI (Mangrove Initiative for Shoreline Habitats & Tangible Incomes) scheme (MoEFCC)**
- ➢ It will facilitate mangrove plantations along India's coastline and on saltpan lands.
- ➢ The programme will operate through "convergence between MGNREGS, Campa Fund and other sources
- ➢ It spreads across 11 States and 2 Union Territories during five years commencing FY 2023-24 onwards
- ➢ It will aim at intensive afforestation of coastal mangrove forests.

- ❖ **मिष्टी (तटीय आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल) योजना ( एमओईएफसीसी )**
- ➢ यह भारत के समुद्र तट और नमक वाली भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करेगा।
- ➢ कार्यक्रम "मनरेगा, कैम्पा फंड और अन्य स्रोतों के बीच अभिसरण" के माध्यम से संचालित होगा
- ➢ यह वित्त वर्ष 2023-24 से शुरू होने वाले पांच वर्षों के दौरान 11 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैल गया है।
- ➢ इसका उद्देश्य तटीय मैंग्रोव वनों का गहन वनीकरण करना होगा।
- ➢ सभी वैश्विक मैंग्रोव प्रति वर्ष 21 मिलियन टन तक कार्बन सोख सकते हैं, जो समतुल्य ऊपरी उष्णकटिबंधीय वनों से लगभग 10 गुना अधिक है।

(I) Deeproot

(II) Root spread over large area

(1)

(i) Gujarat ✓

(ii) Rajasthan

(iii) Andhra Pradesh

(iv) Odisha

## ❖ Paris Club

- The Paris Club, an informal group of creditor nations
- It will provide financial assurances to the International Monetary Fund on Sri Lanka's debt.
- It is a forum of 22 countries (founded in 1956) that act as official creditors and meet to solve payment difficulties faced by debtor countries.
- A debtor country that signs an agreement with its Paris Club creditors, should not then accept from its non-Paris Club commercial and bilateral creditors such terms of treatment of its debt that are less favourable to the debtor than those agreed with the Paris Club.

## ❖ पेरिस क्लब

- पेरिस क्लब, ऋणदाता देशों का एक अनौपचारिक समूह
- यह श्रीलंका के ऋण पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को वित्तीय आश्वासन प्रदान करेगा।
- यह 22 देशों का एक मंच है (1956 में स्थापित) जो आधिकारिक ऋणदाताओं के रूप में कार्य करता है और देनदार देशों के सामने आने वाली भुगतान कठिनाइयों को हल करने के लिए मिलता है।
- सदस्य देश हैं- ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इज़राइल, इटली, जापान, कोरिया, नीदरलैंड, नॉर्वे, रूसी संघ, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका की।

- **Member Countries are- Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Israel, Italy, Japan, Korea, Netherlands, Norway, Russian Federation, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, United States of America.**
- **All 22 are members of the group called Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).**
- **It operates on the principles of consensus and solidarity. Any agreement reached with the debtor country will apply equally to all its Paris Club creditors.**

- **सभी 22 आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) नामक समूह के सदस्य हैं।**
- **यह सर्वसम्मति और एकजुटता के सिद्धांतों पर काम करता है। देनदार देश के साथ किया गया कोई भी समझौता उसके सभी पेरिस क्लब लेनदारों पर समान रूप से लागू होगा।**
- **एक देनदार देश जो अपने पेरिस क्लब लेनदारों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करता है, उसे अपने गैर-पेरिस क्लब वाणिज्यिक और द्विपक्षीय लेनदारों से अपने ऋण के उपचार की ऐसी शर्तों को स्वीकार नहीं करना चाहिए जो पेरिस क्लब के साथ सहमत शर्तों की तुलना में देनदार के लिए कम अनुकूल हैं।**

# UPSC

## ❖ BharOS

- BharOS is a mobile operating system (OS) developed by IIT Madras and funded by the Indian government.
- The project's goal is to reduce the reliance on foreign OSs in smartphones and promote the use of locally developed technology
- BharOS is an Android Open-Source Project and is technically very similar to Android.
- It uses a system called Private App Store Services (PASS) to examine and curate apps that are safe for users.

## ❖ भरोस

- भारओएस आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित और भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम (ओएस) है।
- परियोजना का लक्ष्य स्मार्टफोन में विदेशी ओएस पर निर्भरता को कम करना और स्थानीय रूप से विकसित प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना है
- भारओएस एक एंड्रॉइड ओपन-सोर्स प्रोजेक्ट है और तकनीकी रूप से एंड्रॉइड के समान है।
- यह उन ऐप्स की जांच और प्रबंधन करने के लिए प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विसेज (PASS) नामक सिस्टम का उपयोग करता है जो उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित हैं।

- Users can use other apps as long as they meet BharOS' PASS standards
- BharOS would offer Native Over The Air (NOTA) updates, meaning that security updates and bug fixes will be automatically installed rather than users having to check for updates and implementing them on their own,
- BharOS comes with the No Default Apps (NDA) setting, meaning that users do not have to keep or use pre-installed apps in this mobile operating system

- उपयोगकर्ता अन्य ऐप्स का उपयोग तब तक कर सकते हैं जब तक वे भारओएस के पास मानकों को पूरा करते हैं
- भारओएस नेटिव ओवर द एयर (एनओटीए) अपडेट की पेशकश करेगा , जिसका अर्थ है कि उपयोगकर्ताओं को अपडेट की जांच करने और उन्हें स्वयं लागू करने के बजाय सुरक्षा अपडेट और बग फिक्स स्वचालित रूप से इंस्टॉल किए जाएंगे।
- भारओएस नो डिफॉल्ट ऐप्स (एनडीए) सेटिंग के साथ आता है, जिसका अर्थ है कि उपयोगकर्ताओं को इस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से इंस्टॉल किए गए ऐप्स रखने या उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है।

- **NDA is key as many pre-installed apps that currently ship with other smartphones can slow down the device or take a toll on battery life by acting as bloatware.**

- **एनडीए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई पहले से इंस्टॉल किए गए ऐप्स जो वर्तमान में अन्य स्मार्टफ़ोन के साथ आते हैं, ब्लोटवेयर के रूप में कार्य करके डिवाइस को धीमा कर सकते हैं या बैटरी जीवन पर असर डाल सकते हैं।**

# KHAN GLOBAL STUDIES

## Most Trusted Learning Platform

# THANKS FOR WATCHING